

रजिस्टर्ड नं० एल०-३३/एस० एम०/१३-१४/९६.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, १२ मार्च, १९९६/२२ फाल्गुन, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, ८ मार्च, १९९६

संख्या एल० एल० आर०-डी० (६) २/९६-लेजि०.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख ७ मार्च, १९९६ को अनुमोदित हिमाचल

प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विधिवान्यकरण) विधेयक, 1996 (1996 का 5) को 1996 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि),

1996 का अधिनियम संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1996

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 7 मार्च, 1996 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) का और संशोधन करने और राज्य में अधिकार अभिलेख बनाने या उनको विशेष रूप से पुनरावृत्त करने के सम्बन्ध में की गई कतिपय सार्ववाइयों को विधिमाम्य करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1996 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा सिवाय धारा 2 (ख), धारा 5, धारा 6 और धारा 10 के, जो 23 नितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

1954 का 6

2. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) को धारा 4 में—

धारा 4 का संशोधन।

(क) खण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(4) “बाकीदार” का तात्पर्य भू-राजस्व के बकाया या उसके बदले में किसी धर के लिए दायी व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

- (i) वह व्यक्ति जो प्रतिभू के रूप में बकाया के संदाय के लिए दायी है; और
- (ii) नम्बरदार या कोई अन्य व्यक्ति जिसने भू-राजस्व या उसके बदले में कोई कर संगृहीत किया है किन्तु इसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया है;”;

(ख) खण्ड (5) के उप-खण्ड (ग) में, “राज्यशासन” शब्द के पश्चात् “या धारा 33 के अधीन अभिलेख-अधिकार बनाने या विशेष रूप से पुनरावृत्त करने वाले कलेक्टर” शब्द जोड़े जाएंगे; और

(ग) खण्ड (17) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (18) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(18) “उप-सम्पदा” से तात्पर्य है किसी सम्पदा का उप-खण्ड चाहे उसे किसी भी नाम जैसे तरफ, पत्ती, उप-मोहाल, पन्ना, थोक, खुला से पुनारा जाए और वह उस सम्पदा का भाग होगा;”।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

धारा 16 का संशोधन।

(क) उप-धारा (1) में, “माल अधिकारी” शब्दों से पहले “जहां अभिलेख को देखने से ही कोई गलती या त्रुटि प्रकट है या जहां कुछ तए और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य पाए जाते हैं, वहां” शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“(4) सिवाय किसी आकस्मिक भूत या विलोप से उत्पन्न होने वाली लेखन या गणित सम्बन्धी भूल की दशा के, इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन फाईनेन्शियल कमिश्नर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन नहीं होगा।”।

धारा 32 का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 32 में, उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा (2-क) जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“(2-क) उप-सम्पदा के अधिकार-अभिलेखों के अन्तर्गत इस धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (क), (ग) और (घ) में वर्णित प्रलेख होंगे।”।

धारा 33-क का अन्तः-स्थापन। 5. मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 33-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“33-क. माप की इकाईयों का मीटरी पद्धति पर आधारित होना.—यदि किसी भूमि के अधिकार अभिलेख के माप मीटरी पद्धति में अभिलिखित हैं तो, इस अधिनियम की धारा 33 के अधीन अधिकार-अभिलेख बनाने या अधिकार-अभिलेख की विशेष रूप से पुनरावृत्ति के दौरान, सम्पदा या उप-सम्पदा का पूर्ण पुनर्मापन, वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार, मीटरी पद्धति की इकाईयों के आधार पर किया जाएगा।”।

1976 का
60

धारा 34-क का अन्तः-स्थापन। 6. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 34-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“34-क-किसी सम्पदा का उप-खण्ड.—जहां कहीं भी लोकहित में और इस अधिनियम के उपबन्धों के अबाध कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना समीचीन है, वहां कलेक्टर, राज्यशासन या फाईनेन्शियल कमिश्नर के अनुमोदन से सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के पश्चात्, इस अधिनियम की धारा 33 के अधीन अधिकार अभिलेख बनाने या अधिकार अभिलेख की विशेष रूप से पुनरावृत्ति करने, अध्याय 5 के अधीन भू-राजस्व के निर्धारण और अध्याय 6 के अधीन भू-राजस्व के संग्रहण के प्रयोजन के लिए किसी सम्पदा को एक या अधिक सम्पदाओं या उप-सम्पदाओं में विभाजित अथवा दो या अधिक सम्पदाओं को एक सम्पदा में विलीन कर सकेगा :

परन्तु उप-सम्पदा उस मूल सम्पदा का भाग रहेगी जिसमें से इसे बनाया गया है और ऐसी उप-सम्पदा या सम्पदा का सृजन उस सम्पदा में अधिकारधारकों के अधिकारों को निर्वापित या संपरिवर्तित नहीं करेगा।”।

धारा 36 का संशोधन। 7. मूल अधिनियम की धारा 36 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु राज्यशासन या किसी माल अधिकारी, जो कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, के आदेश के अधीन के सिवाय, पटवारी द्वारा, खण्ड (क) के अधीन सरकारी भूमि के बारे में कोई प्रविष्टि अभिलिखित नहीं की जाएगी।”।

8. मूल अधिनियम की धारा 38 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— धारा 38 का संशोधन ।

(क) राज्यशासन या किसी माल अधिकारी, जो कलेक्टर की पक्ति से नीचे का न हो, द्वारा किए गए आदेश के अनुसार सरकारी भूमि के बारे में प्रविष्टियाँ करना; ”।

9. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 38-क का अन्तःस्थापन ।

“38-क. लेखन भूलों का सुधार.—इस अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में वर्णित किसी अधिकार-अभिलेख या प्रलेखों को बनाने या उनकी विशेष रूप से पुनरावृत्ति के दौरान किसी सम्पदा या उप-सम्पदा के अधिकार अभिलेख में आकस्मिक भूल या विलोप से उत्पन्न होने वाली पाई गई लेखन या गणित सम्बन्धी गलती अथवा त्रुटि जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट है, अभिलेख बनाने वाले या उसकी विशेष रूप से पुनरावृत्ति करने वाले कलेक्टर द्वारा किसी भी समय, स्वतः या किन्हीं पक्षकारों के आवेदन पर, सुधारी जा सकेगी।”।

10. मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 47-क का अन्तःस्थापन ।

“47-क. अनुदेश जारी करने की कलेक्टर की शक्ति.—अधिकार-अभिलेख बनाने या अधिकार-अभिलेख की विशेष रूप से पुनरावृत्ति करने वाला कलेक्टर, फाईनेन्शियल कमिश्नर के अनुमोदन से, माल अधिकारियों/पदधारियों के मार्गदर्शन के लिए, उन सभी विषयों से सम्बन्धित निदेश या अनुदेश जारी कर सकेगा जिनको अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध लागू होते हैं; परन्तु ऐसे निदेश या अनुदेश इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से संगत होंगे।”।

11. मूल अधिनियम की धारा 117 की उप-धारा (2) में, शब्द “दस” के स्थान पर शब्द “पचास” रखा जाएगा । धारा 117 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 171 की उप-धारा (2) में,— धारा 171 का संशोधन ।

(क) खण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(5-क) इस अधिनियम की धारा 33-क के अधीन सम्पदा या उप-सम्पदा के पूर्ण पुनर्माण के बारे में आदेश; ”;

(ख) खण्ड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(6-क) इस अधिनियम की धारा 38-क के अधीन लेखन गलती में सुधार; ”; और

(ग) खण्ड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (12-क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(12-क) इस अधिनियम की धारा 34-क के अधीन, सम्पदा का उप-खण्ड बनाना या उप-सम्पदाओं अथवा सम्पदा आदि का विलयन; ”।

विधिमान्य-
करण।

13. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 और तदधीन बनाए गए नियमों, 1954 का 6 जारी अनुदेशों या अधिसूचनाओं अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अथवा किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, 23 सितम्बर, 1976 के पश्चात् और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1996 के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित भूमि के बारे में यदि अधिकार-अभिलेख बनए गए हैं, या अधिकार-अभिलेख को विशेष रूप से पुनरावृत्त किया गया है तो अधिकार-अभिलेखों का ऐसा बग़ाया जाना या उसकी विशेष रूप से पुनरावृत्ति सदैव विधिमान्य समझी जाएगी और इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि इस अधिनियम की धारा 2 (ख), धारा 5, धारा 6 और धारा 10 द्वारा किए गए संशोधन उस समय प्रवृत्त नहीं थे जब ऐसे अधिकार-अभिलेख बनाए गए थे या विशेषतः पुनरावृत्त किए गए थे।

Act No. 3 of 1996.

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1996

(As Assented to by the Governor on 7th March, 1996)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and to validate certain actions taken in relation to the making or special revision of record-of-rights in the State.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title
and com-
mencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 1996.

(2) It shall come into force at once except sections 2 (b), 5, 6 and 10 which shall be deemed to have come into force on the 23rd day of September, 1976.

Amendment
of section 4.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 of 1954 (hereinafter called the principal Act)—

(a) for clause (4), the following clause shall be substituted, namely:—

“(4) “defaulter” means a person liable for an arrear of land revenue or any tax in lieu thereof and also includes—

(i) a person who is liable as surety for the payment of arrear ; and

(ii) a Numbardar or any other person who has collected the land revenue or any tax in lieu thereof but has not deposited the same into the Government treasury;”;

(b) in clause (5), in sub-clause (c), after the words “State Government”, the words “or the Collector making or specially revising the record-of-rights under section 33” shall be added ; and

(c) after clause (17), the following clause (18) shall be added, namely:—

“(18) “sub-estate” means a sub-division of an estate by whatever name called like a taraf, patti, up-mohal, pana, thok, thula and shall form the part of that estate;”.

Amendment
of section
16.

3. In section 16 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for article and words “A Revenue Officer”, the words “Where there is a mistake or error apparent on the

face of record or where some new and important fact or evidence is discovered, a Revenue Officer" shall be substituted ; and

- (b) after sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:—

"(4) Save in the cases of clerical or arithmetical mistakes arising from any accidental slip or omission, no application for review shall lie under this section against an order passed by the Financial Commissioner under section 17 of this Act."

4. In section 32 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section (2A) shall be added, namely:—

Amendment
of section
32.

"(2A) The record-of-rights for sub-estate shall include the documents mentioned in clauses (a), (c) and (d) of sub-section (2) of this section."

5. After section 33 of the principal Act, the following section 33-A shall be inserted, namely:—

Insertion of
section 33-A

"33-A. *Units of measure to be based on metric system.*—In case the measurements of any land in the record-of-rights are recorded in non-metric system, there shall, during making record-of-rights or special revision of record-of-rights under section 33 of this Act, be a complete remeasurement of the estate or sub-estate based on the units of metric system in accordance with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976."

60 of 1976

6. After section 34 of the principal Act, the following section 34-A shall be inserted, namely:—

Insertion of
section 34-A

"34-A. *Sub-division of an estate etc.*—Wherever it is expedient to do so in the public interest and smooth implementation of the provisions of this Act, the State Government or the Collector, with the approval of the Financial Commissioner, may, after inviting the public objections, divide an estate into two or more sub-estates or merge two or more estates or sub-estates into one estate, for making record-of-rights or special revision of record-of-rights under section 33, assessment of land revenue under chapter-V and collection of land revenue under chapter VI of this Act :

Provided that a sub-estate shall form the part of the original estate out of which it has been formed and the creation of such estate or sub-estate shall not extinguish or modify the rights of right-holders of that estate. "

7. In section 36 of the principal Act, the following proviso shall be added, namely:—

Amendment
of section
36.

"Provided that no entry in respect of the Government land shall be recorded under clause (a) by the Patwari except under the orders of the State Government or of a Revenue Officer not below the rank of the Collector."

Amendment
of section
38.

8. In section 38 of the principal Act, after clause (a), the following clause (aa) shall be added, namely:—

“(aa) making entries in respect of Government land in accordance with the order made by the State Government or by a Revenue Officer not below the rank of the Collector;”.

Insertion of
section 38-A.

9. After section 38 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“38-A. *Correction of clerical errors.*—Clerical or arithmetic mistake or an error apparent on the face of the record, arising from any accidental slip or omission, found in the record-of-rights of an estate or sub-estate during the making of, or special revision of, any record-of-rights or documents mentioned in sub-section (2) of section 32 of this Act, may, either of his own motion or on the application of any of the parties, be corrected by the Collector, making, or specially revising, the record-of-rights.”.

Insertion of
section 47-A.

10. After section 47 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“47-A. *Power of the Collector to issue instructions.*—The Collector making record-of-rights or making special revision of record-of-rights, with the approval of the Financial Commissioner, may, for the guidance of the Revenue Officers/Officials, give directions or issue instructions relating to all matters to which the provisions of the chapters IV and V apply ; provided that such a direction or instruction shall be consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder.”.

Amendment
of section
117.

11. In section 117 of the principal Act, in sub-section (2), for the word “ten”, the word “fifty” shall be substituted.

Amendment
of section
171.

12. In section 171 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) after clause (v), the following clause shall be added, namely:—

“(v-a) order regarding complete remeasurement of an estate or sub-estate under section 33-A of this Act;”;

(b) after clause (vi), the following clause shall be added, namely:—

“(vi-a) correction of clerical errors under section 38-A of this Act;”;

(c) after clause (xii), the following shall be added, namely:—

“(xii-a) formation of sub-division of an estate or merger of sub-estates or estates etc. under section 34-A of this Act;”.

Validation.

13. Notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 and rules, instructions, notifications made or issued thereunder, or in any law for the time being in force or in any judgment, decree or order of any court or other authority, where at any time after the

23rd day of September, 1976 and before the commencement of the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 1996, if any record-of-rights or special revision of record-of-rights has been made in respect of the lands, situated in the State of Himachal Pradesh, such making or special revision of record-of-rights shall, and shall be deemed always to have been valid and shall not be questioned on the ground that the amendments made *vide* sections 2 (b), 5, 6 and 10 of this Act were not in force at that time when such record-of-rights were made or specially revised.